रीमोनीटाइजेशनः अर्थव्यवस्था के लिए गेमचेंजर

पूर्णिमा शर्मा

इसे डिजिटल क्रांति का एक और चरण माना जा सकता है। क्योंकि अब डिजिटल होना विकल्प नहीं प्राथमिक जरुरत बन गया है। यहीं जरुरत भारत को डिजिटल कदमों से तरक्की के एक और पायदान पर ले जाएगी। इंटरनेट के लिए बिजली की जरुरत होती है और भारत पिछले ढ़ाई साल से ही अपने लक्ष्यों में स्पष्ट है, मौजूदा सरकार 2019 तक देश के कोने-कोने तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य लेकर चल रही है

रीमोनीटाइजेशन यानि मुद्रा का बदलाव भारत की अर्थव्यवस्था में लंबी अवधि के बदलाव की शुरुआत है, या कह सकते हैं कि यह घटना भारत में गेमचेंजर साबित होगी।

कई मामलों में शुरुआती तकलीफ दूरगामी सुखद परिणाम देने का आगाज भी है। इस बार सरकार ने राजनीति को ताक पर रखकर आम आदमी के हक में फैसला लेने का जोखिम उठाया है। इस योजना के विरोधी बेहद प्रभावशाली माने जाते हैं, लेकिन सरकार ने उनकी परवाह नहीं की। विरोधी राय रखने वालों ने कई कहानियां गढ़ी कि ये हड़बड़ी में उठाया गया कदम है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को धक्का लगेगा। लेकिन विरोध में दिए गए ये तर्क तथ्यों की रोशनी में बेअसर साबित हो रहे हैं।

साल के अंत तक हालात धीरे-धीरे सामान्य होते दिखे। रीमोनीटाइजेशन के खिलाफ कई तर्क दिए गए। बैंक से पैसा निकालने की सीमा को लेकर भी तर्क दिए गए, लेकिन इस बात को कोई झुठला नहीं सकता कि आम आदमी एक हफ्ते में 24 हजार रुपये और महीने में करीब एक लाख या 96 हजार रुपये से ज्यादा खर्च नहीं करता है। धीरे-धीरे बैंकों के बाहर लाइने भी कम हुई और अब स्थिति करीब-करीब सामान्य हो रही है और इसी के साथ नए साल में एक नया आर्थिक सुधार देश को विकास की दिशा में आगे बढ़ाने चल पड़ा है।

रीमोनीटाइजेशन के विरोध का स्वर कुछ वैसा ही है, जैसा कि कंप्यूटरीकरण के शुरुआती दौर में हुआ था। अस्सी के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने जब आधुनिकता से कदम मिलाने के लिए भारत में कंप्यूटरीकरण की शुरूआत की तो विरोध में यह तर्क दिया गया कि भारत इसके लिए तैयार नहीं है क्योंकि यहां शिक्षा का स्तर नीचा है। साथ ही यह तर्क भी आया कि एक कंप्यूटर कई हाथों का काम छीन लेगा और इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। आज ये सारी आशंकाएं बेबुनियाद साबित हो चुकी हैं। कंप्यूटरीकरण के विरोधी भी अब धड़ल्ले से इस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी भी नए विचार का विरोध एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और दूरदृष्टि रखने वाला कोई प्रशासक ही इसके पार देख पाता है।

प्रधानमंत्री रीमोनीटाइजेशन के जरिए जिन लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं, वे बेहद महत्वपूर्ण और पवित्र हैं। पुराने नोट रद्द करने के पीछे मुख्य लक्ष्य कालेधन की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करना, नकली नोटों को खत्म करना, आतंकवाद की कमर तोड़ना और नशीले पदार्थों के धंधे पर काबू पाना है। अब तक यह प्रक्रिया इन लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में सफलतापूर्वक चल रही है। यही वजह है कि शुरुआती दिक्कतों के बावजूद भारत की आम जनता प्रधानमंत्री के साथ खड़ी है। ऐसे मिलते-जुलते प्रयास करने पर दुनिया के कई देशों में व्यापक उथल-पुथल हो चुकी है। वहीं, भारतीय जनता ने आमतौर पर सरकारी प्रयासों का स्वागत किया है। बैंक कर्मचारियों से लेकर बैंकों के ग्राहकों और कारोबारियों ने इन प्रयासों के महत्व को स्वीकार किया है।

लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं। गत 15 वर्षों से मीडिया में सक्रिय हैं। आज तक, जी बिजनस, डीडी न्यूज जैसे संस्थानों के साथ काम किया है। नीति, शासन व सामाजिक न्याय जैसे विषयों में रुचि है। ईमेल: sharmapurnima1@gmail.com

प्रॉपर्टी की आसमान छूती कीमतें लोगों के अपने घर के सपने को उनकी पहुंच से दूर कर रही थी। रीमोनीटाइजेशन के इस कदम के बाद प्रॉपर्टी मार्केट में जहां कालाधन लगा था, वहां तेज गिरावट देखी गई। प्रॉपर्टी खरीद में सफेद धन के साथ कालेधन के लेन-देन को स्वाभाविक माना जाने लगा था।

ऐसा भी नहीं है कि सरकार के पास कोई योजना नहीं थी और यह सब अचानक हो गया। देश को नगदरहित बनाने की महायोजना की तैयारी के क्रम में देश में प्रधानमंत्री जन-धन योजना के जरिए करीब 25 करोड़ नए बैंक खाते खोले जा चुके है। यानि हर घर को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने की तैयारी तो बहुत पहले ही हो चुकी थी और अब कहा जा सकता है कि अमूमन हर घर में एक बैंक खाता है। सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे लोगों के अकाउंट में पहुंचाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। भ्रष्टाचार रोकने का यह रामबाण उपाय है क्योंकि इसमें मध्यस्थ यानि बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाती है। इन खातों के आधार संख्या से जुड़े होने के कारण भी सरकारी पैसा लक्षित व्यक्ति तक ही पहुंचेगा, इसकी संभावना बहुत अधिक है। ऐसे में बैंकिंग सेवाएं हर घर की पहुंच में है और अब अगला कदम डिजिटल बैंकिंग को लोगों तक पहुंचाना है। रीमोनीटाइजेशन के कदम को विस्तार से देखें तो लंबी अवधि में ये कई संभावनाओं के द्वार खोल रहा है।

सबसे पहले नजर डालते हैं आम आदमी के घर के सपने पर। देखा जाए तो घर खरीदना आम आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा था। प्रॉपर्टी की आसमान छूती कीमतें लोगों के अपने घर के सपने को उनकी पहुंच से दूर कर रही थी। रीमोनीटाइजेशन के इस कदम के बाद प्रॉपर्टी मार्केट में जहां कालाधन लगा था, वहां तेज गिरावट देखी गई। प्रॉपर्टी खरीद में सफेद धन के साथ कालेधन के लेन-देन को स्वाभाविक माना जाने लगा था। इस वजह से कालेधन के स्वामी एकाधिक बेनामी संपत्ति खरीद पा रहे थे। नतीजतन, प्रॉपर्टी बाजार में कृत्रिम मांग पैदा हो गई थी। इसके परिणामस्वरूप घर खरीदना महंगा हो गया था। अब आम लोगों के लिए अपने आशियाने का सपना साकार करने की दिशा में ये बेहतरीन कदम साबित हो सकता है। कहा जा रहा है कि प्रापर्टी मार्केट पर इसका खासा असर पड़ा है और आम आदमी के लिए ये एक अच्छी खबर है। रीमोनीटाइजेशन के बाद, अब ये कहा जा रहा है कि प्रॉपर्टी अभी और संतुलित होगी।

जब हम नगदरहित होने की बात करते हैं तो हमें ये भी ध्यान देना होगा कि दुनिया किस तरफ जा रही है और हम कहां है। यूरोपीय देशों की बात करें तो वहां नगद जीडीपी का करीब 2-3 प्रतिशत ही है जबकि हमारे देश में नगद जीडीपी का 12.5 प्रतिशत है। और इस अंतर को पाटने के लिए कुछ कड़े कदमों की जरुरत थी, क्योंकि बदलाव अपने आप नहीं होते। कई बार सकारात्मक दूरगामी परिणामों के लिए उन्हें सख्ती से लागू करना पड़ता है। अगर गौर करें तो देखेंगे कि हर अवैध काम नगद में ही होता आया है। देश के नगदरहित की दिशा में उठते कदमों ने कई अपराधियों के हाथ से हथियार छीन लिए हैं। इस दौरान, चाहे कश्मीर में आतंकवाद की बात हो या फिर ड्रग्स या मानव तस्करी की, रीमोनीटाइजेशन ने कई बड़े अपराधों की ऑक्सीजन आपूर्ति बंद कर दी। कालेधन का कारोबार, कर चोरी जैसे कई अपराध नगद की पनाह में ही जन्म लेते थे क्योंकि नगद का कोई सबूत नहीं होता।

दूसरी ओर ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि अब देश में डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र का विस्तार होगा। डिजिटल सेवाओं क्षेत्र में विस्तार से वहां नौकरियां भी बढ़ेंगी। क्योंकि अब देश के हर गांव-गांव तक इंटरनेट-मोबाइल पहुंचाना होगा। इसे डिजिटल क्रांति का एक और चरण माना जा सकता है। क्योंकि अब डिजिटल होना विकल्प नहीं प्राथमिक जरुरत बन गया है। यहीं जरुरत भारत को डिजिटल कदमों से तरक्की के एक और पायदान पर ले जाएगी। इंटरनेट के लिए बिजली की जरुरत होती है और भारत पिछले ढ़ाई साल से ही अपने लक्ष्यों में स्पष्ट है, मौजूदा सरकार 2019 तक देश के कोने-कोने तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य लेकर चल रही है।

अब तक पिछली किसी भी सरकार ने अर्थव्यस्था को नगदरहित बनाने की दिशा में नहीं सोचा था। लेकिन पहली बार देश में ऐसा साहसिक कदम उठाया गया। परिवर्तन के इस मोड़ पर, हम एक ऐसे युग में कदम रखने जा रहे हैं जहां हमें तकनीक को चुनौती नहीं सहायक के रूप में देखना और समझना होगा। इसे देश में डिजिटल विस्तार की नई लहर कह सकते हैं। जैसे-जैसे देश डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ता रहा है हमें अपनी आईटी अवसंरचना भी मजबूत करनी होगी, इंटरनेट नेटवर्क का विस्तार करना होगा, नई ब्रॉडबैंड की लाइन्स बिछानी होंगी जिसमें गुणवत्ता और गति भी बढ़िया हो। रीमोनिटाइजेशन के बाद डिजिटल इंडस्ट्री का भी तेजी से विस्तार होगा। इस समय भारत में 36 प्रतिशत क्षेत्र तक ही इंटरनेट की पहुंच है, हमें जल्द से जल्द इंटरनेट सूदूर इलाकों तक पहुंचाना है।

देश के नगदरहित की दिशा में उठते कदमों ने कई अपराधियों के हाथ से हथियार छीन लिए हैं। इस दौरान, चाहे कश्मीर में आतंकवाद की बात हो या फिर ड्रग्स या मानव तस्करी की, रीमोनीटाइजेशन ने कई बड़े अपराधों की ऑक्सीजन आपूर्ति बंद कर दी। कालेधन का कारोबार, कर चोरी जैसे कई अपराध नगद की पनाह में ही जन्म लेते थे क्योंकि नगद का कोई सबूत नहीं होता।

बदलाव के साथ, हमें अपने संसाधन बढ़ाने हैं, आम लोगों के डिजिटल विनिमय सिखाना होगा। ऐसे में हमें डिजिटल उद्योगों के लिए और हाथों की जरुरत होगी- यहां नौकरियों के अवसर तेजी से बढ़ेंगे। यहां कॉरपोरेट क्षेत्र को आगे आकर अपना सीएसआर या कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साधनों का प्रयोग देश को डिजिटल मजबूती देने के लिए करना चाहिए। अब देश में ज्यादा डिजिटल प्रोजेक्टस पर काम करने की आवश्यकता बढ़ गई है, और डिजिटल साक्षरता बढ़ाने और सिखाने की भी। कुल मिलाकर रीमोनिटाइजेशन देश हित में उठाया गया एक ऐसा कदम है जिसके दूरगामी परिणाम सकारात्मक होंगे, आर्थिक सुधारों की दृष्टि से इसे लंबी रेस का घोड़ा कहा जा सकता है। ❑